

ई-गवर्नेन्स योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु बजट पाविधान

(रु. लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2017-18 के प्रस्तावित बजट		अभ्युक्ति
		प्राप्तियों के अनुमान बजट के माध्यम से	व्यय अनुमान	
1	2	3	4	5
(क)	नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान (के. 50% / रा. 50%)			
1	स्टेट डाटा सेंटर	1474.50	1474.50	<ul style="list-style-type: none"> -फैसिलिटी मैनेजमेन्ट सिस्टम-ओपेक्स हेतु टीसीएस को भुगतान। -अवशेष कैपेक्स हेतु टीसीएस को भुगतान। -थर्ड पार्टी आडिटर हेतु। -कम्पोजिट टीम जनशक्ति की सेलरी। -विद्युत व डीजल पर व्यय। -बैण्डबिड्य (रिडन्डन्ट इण्टरनेट लीज्ड लाइन हेतु) -एडमिनिस्ट्रेटिव एवं कन्टिनजेन्सी। -ऑरेकल आठ कोर नाइसेन्स की आपूर्ति। -स्टेट डाटा सेंटर सृजित क्षमता के अधिकतर उपयोग हो जाने एवं विभागों से मांग किये जाने वाले स्पेस को ध्यान में रखते हुये सेंटर के इनहान्समेन्ट/अपग्रेडेशन की आवश्यकता हेतु।
	कुल योग (क) (रु०)	1474.50	1474.50	

(ख)	उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान			
1	स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान – यू.पी. नेट)	2500.00	2500.00	–निक्सी को ओपेक्स –एफ.एम.एस. हेतु। –बी.एस.एन.एल. को ए.एम.सी., बैंडविड्थ तथा मोडम किराय हेतु। –थर्ड पार्टी आडिटर हेतु।
(ग)	आई.टी. पूल फण्ड की स्थापना	250.00	250.00	प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान किया जाना सरकार की प्राथमिकताओं में शीर्ष स्थान पर है। ऐसे विभाग जिनके पास आई.टी. सेवाओं के विकास के लिये संसाधनों की कमी है एवं ऐसी सेवाओं के लिये पूर्व में बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है, ऐसे विभागों एवं सेवाओं के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु बजट में प्राविधानित/प्रस्तावित इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
	कुल योग (क+ख+ग) (रु०)	4224.50	4224.50	